भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3411

23 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

टियर-।। और टियर-।।। शहरों के लिए कम लागत वाली एमआरटीएस को अपनाना

3411 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024) की इस समुक्ति की जांच की है कि मेट्रो रेल परियोजनाएं बहुत अधिक पूंजी गहन होती हैं और अक्सर छोटे तथा उभरते शहरों में आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होती हैं;

(ख) क्या टियर ॥ और टियर - ॥ शहरों के लिए बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी), लाइट रेल ट्रांजिट (एलआरटी) और क्षेत्रीय रेल जैसे कम लागत वाले मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को प्राथमिकता देने संबंधी समिति की सिफारिश पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ऐसे शहरों के लिए परिवहन निवेश को दिशा देने हेतु एकीकृत शहरी आवागमन योजनाएं तैयार करने का विचार रखती है; और

(घ) इन शहरों में एमआरटीएस के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडलों की संभावना तलाशने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) शहरी नियोजन राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारें विभिन्न परिवहन साधनों के एकीकरण सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने और उसे शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं। आवासन और शहरी का मंत्रालय (एमओएचयूए) ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) 2006 और मेट्रो रेल नीति, 2017 जैसी नीतियां जारी की हैं, जो राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं ताकि शहरी परिवहन प्रणालियों

का नियोजन और कार्यान्वयन सबसे स्थायी और व्यवहार्य तरीके से किया जा सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमएओएचयूए) "मेट्रो और गैर-मेट्रो परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण" नामक उप-योजना के तहत कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और अन्य व्यवहार्यता परिवहन अध्ययनों से संबंधित गतिविधियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से प्रस्ताव प्राप्त होने पर 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि मेट्रो रेल नीति, 2017 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वित्तपोषण मॉडल का समर्थन करती है, जिसमें संचालन और रखरखाव में भी निजी क्षेत्र के भागीदार शामिल हैं।

*****